



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 7 मार्च, 2005/16 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 7 मार्च, 2005

राज्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-17-2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहताएं हटाना)

संशोधन विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-2) जो आज दिनांक 7 मार्च, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
राचिव ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) संशोधन विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) संशोधन अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 24 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ख-क) जोड़ा जाएगा, संशोधन।
अर्थात् :—

“(ख-क) मुख्य मन्त्री के राजनैतिक सलाहकार का पद ;”।

3. (1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) संशोधन अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 2005 के अध्यादेश संख्यांक 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसित किए गए अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी। का निरसन और व्यावृत्तियां।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा सदस्यों में से, मुख्य मंत्री के राजनैतिक सलाहकार की नियुक्ति का मामला विचाराधीन था। परन्तु किसी सदस्य की इस प्रकार की नियुक्ति विधान सभा की सदस्यता के लिए ऐसे सदस्य को इस तथ्य के आधार पर निरहित करती है कि वह लाभ के पद पर है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहताएं हटाना) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन कोई व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर निरहित नहीं होगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन इस धारा के खण्ड (क) से (घ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लाभ के पदों में से किसी का धारक है।

इस प्रकार किसी सदस्य की, मुख्य मंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्ति पर, उसे हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्यता हेतु निरहित होने से रोकने के लिए उपर्युक्त अधिनियम का यथोचित रूप से संशोधन करना और मुख्य मंत्री के राजनैतिक सलाहकार के पद को धारा 3 में शामिल करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहताएं हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 7) में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहताएं हटाना) संशोधन अध्यादेश, 2005 (2005 का 1) को 22 जनवरी, 2005 को प्रख्यापित किया। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

शिमला:

तारीख, 2005.

वीरभद्र सिंह,

मुख्य मंत्री।

वित्तीय जापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सन्बन्धी जापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) संशोधन विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरहंताएं हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख, 2005

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS
(REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) AMENDMENT BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members
(Removal of Disqualifications) Act, 1971 (Act No. 7 of 1971).*BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh
in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follow :—Short title
and com-
mencement.1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative
Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Act,
2005.(2) It shall and shall always be deemed to have come into
force on the 24th day of January, 2005.Amendment
of section
3.2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assem-
bly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971, after clause (b),
the following new clause (b-a) shall be added, namely :—“(b-a) the office of the Political Advisor to the Chief
Minister;”.Repeal of
Ordinance
No. 1 of
2005 and
savings.3. (1) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members
(Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 2005, is
hereby repealed.(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action
taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have
been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The matter of appointment of the Political Advisor to the Chief Minister, from amongst Members of the Legislative Assembly, was under consideration. But appointment of any Member as such attracted disqualifications of such member for membership of the Legislative Assembly only for the fact that he holds office of profit. Under section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971, a person shall not be disqualified for being chosen as and for being a member of Himachal Pradesh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the offices of profit as specified under clauses (a) to (s) of this section, under the Government of India or the Government of any State.

Thus in order to prevent disqualification of any member for membership of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh on his appointment to the office of the Political Advisor to the Chief Minister, it became necessary to amend the Act *ibid* suitably and to include the office of the Political Advisor to the Chief Minister in section 3.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 (Act No. 7 of 1971) was required to be carried out urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 2005 (1 of 2005) on the 22nd January, 2005. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:

The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS
(REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) AMENDMENT BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 (Act No. 7 of 1971).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The, 2005.